PAPERS LAID ON THE TABLE

PEPSU RULES OF EXECUTIVE BUSINESS (VALIDATION) ACT

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Datar): I beg to lay on the Table a copy of the Patiala and East Punjab States Union Rules of Executive Business (Validation) Act, 1954 (President's Act No. 6 of 1954), under sub-section (3) of section 3 of the Patiala and East Punjab States Union Legislature (Delegation of Powers) Act, 1953. [*Placed in the Library. See No.* S-82/54].

SPECIAL MARRIAGE BILL

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide a special form of marriage in certain cases, and for the registration of such and certain other marriages.

GENERAN BUDGET—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now continue the general discussion on the General Budget.

As the House will be sitting today till 7-30 p.m., the Private Members' Business will be taken up from 5-00 p.m. to 7-30 p.m. instead of from 4-30 p.m. to 7 p.m.

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित,—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि पांच वर्षों के बाद हमें यह देखने को मिल रहा है कि हमारी आर्थिक और उद्योगीकरण की व्यवस्था में बहुत फर्क हो रहा है । हमारे यहां के ३६ करोड़ लोगों में से ३५ करोड़ लोगों का इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है । हमारे अनुभवी लोग अमरीका और रूस और चीन से हमारी तुलना करते हैं पर वह यह भूल जाते हैं कि अगर संसार का हर एक देश यंत्रीकरण की ओर झुक जावे और हर एक देश उद्योग की ओर झुक जावे तो संसार में कौन सा देश उनकी चीजों को खरीदने के लिये तैयार होगा और कैसे सारा सामान बाहर के देशों में वितरित हो सकेगा । आप देखें कि उत्तर अमरीका की जनसंख्या कितनी है । मैं समझता हूं कि अगर कोई भी देश उसके माल की खपत न करे तो भी उनके पास इतने खनिज पदार्थ हैं और जन संख्या इतनी कम है कि वह अपने पर निर्भर रह सकते हैं । अगर आप रूस और चीन की तुलना करें और उनकी संख्या को देखें तो आप पायेंगे कि यद्यपि चीन में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन चीन और रूस दोनों का साम्यवाद की तरफ झुकाव है और रूस के पास साइबेरिया का इतना बड़ा प्रदेश है कि उसका क्षेत्रफल हिन्दुस्तान से पांच गुना है और उसका उपयोग करके वह आत्म निर्भर हो सकता है । इस लिये हम हिन्दुस्तान के गृह-उद्योग की अमरीका और रूस और चीन से पूरे तौर पर तुलना नहीं कर सकते । मैं इस बात के पक्ष में हूं कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं और जो खासकर डिफेंस से सम्बन्धित उद्योग हैं, या रेल और जो दूसरे बड़े बड़े उद्योग हैं उनको सरकार ले और उनका यंत्रीकरण हो । इन उद्योगों को इस प्रकार बढ़ाया जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जहां तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है उनका विकेन्द्रीकरण होना नितान्त आवश्यक है । यह होगा तभी हम अपने देश के करोड़ों लोगों को काम दे सकेंगे । आज हमारे देश में एक आदमी के पास करोड़ों रुपये की पूंजी रहने दी जाती है जिससे वह जिस तरीके से चाहे दूसरे के लिये कठिनाई पैदा कर सकता है । आप देखिये कि जमींदारी उन्मूलन के बाद गांव में जो रुपये वाले हैं वह अपने रुपये और अनाज को न मालूम किस कोने में रखे हुये हैं और उसको दबाये बैठे हैं वे देहातियों को काम नहीं देते, बल्कि ताना

मारते हैं कि जाओ कांग्रेस वाले रुपये अनाज देंगे । आज गांवों में करोड़ों लोगों को काम नहीं मिलता है । इसलिये वह बड़े बड़े शहरों में बड़े उद्योगों में काम करने के लिये जाते हैं । वहां एक मजदूर को ७० या ८० रुपया महीना मिलता है लेकिन खोजने पर भी ३० या ३५ रुपये महीने में एक छोटा सा कमरा नहीं मिलता । तो इन मुसीबतों में आज गांव वालों को शहरों में जाना पड़ता है ।

आज लोग कहते हैं कि मध्यम श्रेणी के लोगों को काम नहीं मिलता । लेकिन आज उनसे अधिक देहात वालों की हालत खराब है । वह उन से ज्यादा बेकार हैं न उनका संगठन है, न उनकी आवाज बुलन्द हो पाती है और न वे पढ़े लिखे हैं । और आज तक उनका मसला हल नहीं होता तब तक हमारी सरकार को शांति से नहीं बैठना चाहिये । उनके लिये कोई न कोई कदम उठाना चाहिये एक ओर कुछ लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें हैं और दूसरी ओर करोड़ों में से प्रत्येक के पास दो दो एकड़ भी जमीन नहीं है । इस लिये मैं कहता हूं कि जमीन का बटवारा जल्द से जल्द होना चाहिये । अब लोगों ने जमीन के बटवारे से अपने को बचाने के लिये कानूनी दांव पेंच सीख लिये हैं और वह पटवारियों और सरकारी कर्मचारियों से मिलकर अपने बेटों और भतीजों के नाम जमीन को दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस बात का निर्धारण होना चाहिये कि प्रति व्यक्ति को कितनी जमीन दी जाय । और प्रदेशीय सरकारों को आदेश जारी किये जायें कि किसानों को काश्तकारी के लिये जमीन मिले । सिद्धांत तो यह होना चाहिये कि जो जमीन को जोतता है उसी की जमीन होनी चाहिये और जो खाली बैठा रहत है और दूसरों के सहारे पूंजी एकत्रित करता है और शहर या दूर गांव में बैठ कर खेती करावे उसकी जमीन नहीं होनी चाहिये । इसी प्रकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के धन में भी राशनिंग की जावे ।

अब मैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामूहिक विकास योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । यह कार्य अच्छा चल रहा है । स्कूल खोले जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहीं हैं और दूसरे उन्नति के काम किये जा रहे हैं । परन्तु एक कमी है । वहां पर गृह-उद्योग की कोई स्कीम नहीं है । हमारे वित्त मंत्री हमको इस के आंकड़े दें कि आज तीन वर्ष हो गये उसमें ७४ सामूहिक विकास योजनाओं और ६०० राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में इस ओर कितना काम हुआ है कितने लोग गृह-उद्योग में स्वावलम्बी बन चुके हैं । आज नहीं तो वह हमको यह आंकड़े दो साल बाद बतलावें कि कितने आदमी स्वावलम्बी बने । यह बता देना तो मैं समझता हूं उनके लिये बहुत जरूरी होगा ।

इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार तो एस्टीमेट बनाती है, अनुमान लगाती है कि हमारी योजना पर इतना रुपया खर्च होगा । आपको मालूम होगा कि कई बार पब्लिक एकाउंट कमेटी और अनुमान कमेटी ने यह बतलाया है कि क्रमशः प्रत्येक वर्ष योजनाओं का खर्च अनुमान बढ़ता ही जा रहा है । आज इस बात को कहने में कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जो हमारे ठेकेदार हैं उनके कारण इस मामले में हम बदनाम होते हैं और दूसरे लोग हमको बदनाम करते हैं । चाहे सरकारी कर्मचारी कुछ न करते हों, सरकार कुछ न करती हो, लेकिन यह ठेकेदार वास्तविक से कहीं कई गुना अधिक

[श्री जांगड़े]

अनुमान, सरकारी कर्मचारियों से मिलकर बना लेते हैं और करोड़ों रुपया बरबाद कर देते हैं। यदि वह रुपया बच जाय तो वह दूसरी योजनाओं में लागया जा सकता है और हमको डेफिसिट फाइनेनर्सिंग की और यू० एन० ओ० से सहायता लेने की और नेशनल सेविंग की कोई जरूरत न पड़े। हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना साहब कहते हैं कि उनके पास स्कीमें तो बहुत हैं पर उनकी पाकेट खाली है। अगर यह रुपया बच जाय तो उनको यह बात कहने की जरूरत नहीं होगी।

Mr. Speaker: Order, order. I might request the hon. Member that he should address the Chair. That is the proper parliamentary convention.

3P.M.

श्री जांगड़े : अध्यक्ष महोदय क्षमा करें। मैं कुछ शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि यदि कुछ सालों के लिये इस शिक्षा पद्धति को रोक दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि अगर हम इस पद्धिति को जारी रखेंगे तो हम बेकारों को बहुत बढ़ा देंगे क्योंकि यह शिक्षा केवल मानसिक ज्ञान देती है, शारीरिक ज्ञान नहीं देती। आज मिडिल पास करने वाला विद्यार्थी भी केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार और स्थानीय संस्थाओं की ओर नौकरी के लिये देखता है। आज जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं वह मुंशियों के कारखाने बनी हुई हैं और उनको परावलम्बी बनाती हैं और वह सरकार के लिये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। चार पांच साल हो गये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में सारे देश में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।

हम देहातों में सड़क बना रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं, लेकिन वहां के लोग अब भी गरीब बने हुये हैं क्योंकि देहात का आर्थिक ढांचा नहीं बदला। हम चाहते हैं कि देहात के लोग शहरों की ओर न जांय। शहरों में जो जन संख्या है वह अब न बढ़ने पाये और देहात हरे भरे बनें। जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, go back to the villages गांव की ओर पुन: जाओ जैसा कि सर्वोदय सिद्धांत कहता है उसी सिद्धांत को, गो पालन और गोसंवर्द्धन के सिद्धांत को भी हमें पूर्ण करना है। गांव के लोग गांव में ही रहें और गांव का पशु संवर्धन ही राम राज्य स्थापित हो लोग स्वावलंबी हों, यही हम को करना है। गांव का जो काम काज हो और जिन चीजों की वहां जरूरत हो, वह गांव में ही तैयार हों। इस तरह से काम करें तभी जाकर हम गांव के किसानों को सुखी बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां दो प्रश्नों का समाधान चाहता हूं। अभी हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के उपर भारत का कर्जा है। पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अपने बजट सत्र में यह नहीं कहा कि हम हिन्दुस्तान को इतना अदा करने वाले हैं। पाकिस्तान को इतना रुपया अदा करना है, इस सम्बन्ध में वह बिल्कुल चुप रहे। इस बाबत में हिन्दुस्तान क्या करने वाला है यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं स्टर्लिंग बैलेंसेज के बारे में जानना चाहता हूं। स्टर्लिंग बैलेंसेज हमारे विलायत में बहुत ज्यादा हैं और स्टर्लिंग बैलेंसेज का उपयोग भारत को अपने प्लान और उन्नति के लिये करना है। वह रुपया हमको कितने वर्षों में मिलने वाला है और कब तक मिलने वाला है

qif^RcTPT

किस तरह मिलने वाला है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

इस के उपरान्त मैं आप के सामने मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि चमड़े का जो उद्योग है, उस में खास चीज यह है कि नुकसान हमारे गरीब भाइयों को पहुंच रहा है, क्योंकि चमड़े के उद्योगों को यंत्रीकरण का रूप दिया जा रहा है । आज हमारे लाखों लोग, बेकार हो रहे हैं । उन को कोई सुरक्षा, कोई बढ़ावा, नहीं दिया जा रहा है । आज हम अमुक अमुक जगहों से चमड़ा मगाते हैं और साथ ही यह बात भी है कि हम अमुक अमुक चमड़े को चीन जैसे देशों को निर्यात भी करते हैं । तो यह कैसी उल्टी बात है, यह मैं समझना चाहता हूं । इस के लिये सरकार को देखना चाहिये ।

अब मैं सोप इंडस्ट्री, साबुन के बारे में कहना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल गृह-उद्योग में बनाये जाने वाले साबुन को ही नहीं, बल्कि आधुनिक तर्ज से चिकनाई में कोई यन्त्र का उपयोग करते हैं तो उनको भी कर से मुक्त करना चाहिये ।

अन्त में मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आप को मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में प्रत्येक प्रदेश में बड़ी बड़ी योजनायें चल रहीं हैं, प्रत्येक प्रदेश को कुछ न कुछ रकम केन्द्र से मिलती है । परन्तु मध्य प्रदेश को कुछ भी नहीं मिलता । न वहां कोई नदी घाटी योजना है और न कोई बड़ा कारखाना है, न प्लान में कोई बड़ी चीज वहां के लिये रक्खी गई है । आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के जो तीन जिले हैं जो मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बहुत से कमी वाले प्रदेशों को सौ साल से अनाज, चावल, प्रदान करता रहा है, उस की ओर सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया । उन जिलों की हालत को सुधारने के लिये और उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या किया गया ? अभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया यह मैं आपको बताना चाहता हूं । पता नहीं प्रांतीय सरकार ने कुछ किया है या नहीं, पर भारत सरकार ने नहीं किया । वहां की वास्तविक बात मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां छत्तीसगढ़ के इन तीन जिलों में ६० लाख की जन संख्या है, उस में से दस बारह लाख लोगों के क्षेत्रफल में अकाल पड़ा हुआ है । आज वहां से हजारों लोग खड़गपुर कलकत्ता की पलारी वगैरह की तरफ भाग रहे हैं क्यों कि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं । आप को मालूम होगा कि वहां दस दस पंद्रह लाख लोगों के बीच में जो बस्ती है, वह जो वहां का क्षेत्रफल है, वहां पर १२ वर्षों में पांच बार अकाल पड़ चुका है, पर किसी भी सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने या किसी भी सरकार ने, उस ओर ध्यान नहीं दिया । इस कारण से हम हिन्दुस्तान के अन्न के अभाव को दूर नहीं कर सकते । हम को इस लिये इस ओर ध्यान देना चाहिये । प्रांतीय सरकार ध्यान दे या न दे, पर केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान का वह एरिया जो ग्रैनरी रहा है, जो मध्य-प्रदेश हिन्दुस्तान का ग्रैनरी रहा है, और जहां से लाखों टन चावल दूसरे प्रांतों को दिया जा रहा है, उसकी उपेक्षा न की जाय । इस के लिये मैं केन्द्रीय सरकार से बिनती करता हूं कि वहां माइनर इरिगेशन छोटी सिंचाई की योजनाओं को चालू करे । प्रांतीय सरकार खर्च करे या न करे, लेकिन केन्द्रीय सरकार को इस के लिये प्रयत्न करना चाहिये, तभी हम अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां मध्य प्रदेश के लिये कोई भी योजना नहीं है, न इरिगेशन प्लान है, न आयरन स्टील फैक्टरी हीं

[श्री जांगड़े]

कोई वहां के लिये है। मैंगनीज के सम्बन्ध में भी शायद २० लाख का प्लांट खोला गया है, इस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की हमेशा उपेक्षा की जाती है, क्योंकि यहां पर उनकी तरफ से बोलने वाले सदस्य नहीं हैं, उनकी आवाज़ बुलन्द नहीं होती और न वहां की प्रान्तीय सरकार की ही आवाज बुलन्द होती है। इस लिये मध्य प्रदेश को नगण्य माना जाता है। इस के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह मध्य प्रदेश की ओर अधिक ध्यान दें।

श्री चाबदा (बनस्कंठा) : अध्यक्ष जी, मैं पिछले दो तीन दिनों से बजट के ऊपर जो आलोचना हो रही है, बजट के पक्ष में और उसके विरोध में, उस को ध्यान से सुनता रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि आज के जो हमारे माली हालात ह, और देश की जो दूसरी परिस्थितियां हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुये अगर बजट को देखा जाय तो मैं यही कहूंगा कि हम देश के विकास की ओर स्थिरता और संयम से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हद तक तो मैं यहां तक कहूंगा कि हमारा बजट एक क्रांतिकारी बजट भी कहला सकता है। कुछ बातें बजट में ऐसी हैं कि जिनके लिये हम कह सकते हैं कि इस में कुछ रद्दोबदल किया जाय।

आज नौबत यह आ गई है कि बाहर से प्रदेशों की हमें कितनी मदद मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सब सोचना पड़ रहा है। फिर डैफिसिट फाईनेन्स की ओर भी हम जा रहे हैं और कुछ टैक्सेज भी ऐसे लगाने को हम लुभा गये हैं कि जो नहीं लगाते तो अच्छा होता।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

इन सब बातों को देखते हुये हमें कुछ चिन्ता सी होती है कि जो हमारे विकास का काम है, जो हमारा प्लान का काम है, वह इस तरह हम कैसे बढ़ा सकेंगे। मैं इस विषय में तो अधिक नहीं जानता कि यह कहां तक संभव हो सकती है, लेकिन एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारा देश मुश्किल में है और हम अपना विकास करना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पर देश में जितना भी धन हो, जो कोई काम में न आ रहा हो, करीब करीब जो सड़ रहा हो, ऐसा धन हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। वह धन या तो राजा महाराजाओं के पास है, या बड़े बड़े धनी सेठ साहूकारों के पास है। और बहुत सा धन ऐसा है कि जो मस्जिदों और मन्दिरों के पास है, मठों के पास है। हम यह करके किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और न किसी की धार्मिक भावना को दुखाना चाहते हैं। लेकिन वह ऐसा धन इतना धन है कि जिस से हमारे तीन चार प्लान आसानी से बगैर किसी तकलीफ के चलाये जा सकते हैं। वह धन जिनके पास है उन से हम को विनती कर के लेना चाहिये। हम ने अभी राजप्रमुखों और राजाओं से विनती की थी कि वे अपनी पैनसन में से दस टका बा खुशी कट करवा दें। ऐसे ही हम ऐसी संस्थाओं से कि जहां पैसा पड़ा सड़ रहा है, वह भले ही अपने उपयोग के लिये, अपने कार्य के लिये उसको रखे हों, फिर भी जो पैसा पड़ा हुआ है, उसको अगर वह हमें बगैर ब्याज के लोन पर दे सकें तो अच्छा है, नहीं तो कुछ मामुली ब्याज से भी दें, इस के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। इस में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिये।

मैं अब अनएम्पलायमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अनएम्पलायमेन्ट के हम दो विभाग कर सकते हैं। एक तो शहरी बेकारी है और दूसरी ग्राम्य बेकारी है।

शहरी बेकारी के लिये तो प्लान में काफी गुंजायश है, और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब भी और हमारे कामर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब भी, इसके लिये काफी सचेत रहते हैं कि कैसे इस बेकारी को कम किया जाय। लेकिन जहां तक ग्राम्य बेकारी का सवाल है, उसके ऊपर हमें ज्यादा गौर करना चाहिये। मैं एक मामूली सी मिसाल दूंगा कि ग्राम्य बेकारी किस तरह की है और वह कैसे बढ़ती है। आज तक गांव में खेती के अलावा कई पूरक धंधे किसानों के हाथ में थे। उन मे एक सब से बड़ा उद्योग जो उन के हाथ में था वह किराये पर बैलगाड़ी चलाने का था। वह जब खेती के काम से फारिग हो जाते थे तो किराये से बैलगाड़ी चलाते थे, और उससे कुछ पैसा कमा लेते थे, जिस से वह खेती के लिये बीज और दूसरे खेती के साधन वगैरह जुटा लेते थे। आज गांव गांव में पब्लिक कैरियर मोटर लारियां हो जाने से वह काम उन का बिल्कुल टूट गया है। मैं एक मिसाल दूंगा कि एक मोटर लारी जो ४ टन वजन लेकर १०० मील जाती है, एक दिन में, तो उसका असर जो किराये से बैल गाड़ी चलाने वाले हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है। इस से आप को अन्दाजा होगा कि ग्राम्य बेकारी कितनी बढ़ती है। एक मोटर लारी जो १०० मील ४ टन अनाज लेकर एक दिन में जाती है, उस के असर से नौ बैलगाड़ियां, १८ बैलगाड़ियों के साथ काम करने वाले इन्सान दस दिन के लिये बेकार हो जाते हैं। अगर एक इन्सान के पीछे पाच इन्सानों का कुनबा परिवार, हम समझें तो ९० आदमी एक साथ एक दिन में एक लारी के १०० मील जाने से बेकार हो जाते हैं। उनको खाने को नहीं मिलता। अब इसके साथ साथ गाड़ी बनाने वाले, लकड़ी के काम में लगने वाले, बैलों का काम करने वाले, गांव में जो दूकानों का काम करते हैं, इन सब पर इसका असर पड़ता है, उनको काम नहीं मिलता। इस तरह ग्राम्य बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है। यह तो उन किसानों की बात है कि जो खेती करते करते यह काम करते हैं। इस के अलावा और भी कई लोग हैं जो ऊंटों पर, घोड़ों पर, गधों पर और बैलों पर भी बोझ ढोते हैं, और हमारी तरफ, खास कर राजस्थान में, हजारों बैलों की कमर पर बोझ रखकर वजन ढोया जाता है। वह सब आदमी इस तरह बेकार हो गये हैं और इन पशुओं को सिवाय कत्लखाने में जाने के और कोई चारा नहीं रहा। तो यह तो एक मामूली सी बात है।

ऐसे ही तेल के घानी की समस्या है। बड़े बड़े इंजिन हम लगाने की इजाजत दे देते हैं और कई इस तरह के काम हैं जो कि मशीनरी से होते हैं, उस की वजह से यह ग्राम्य बेकारी बहुत बढ़ती जाती है।

अब आज मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में देखा कि यह बताया गया है कि गवर्नमेंट कहीं विलेज इंडस्ट्रीज की प्रोत्साहन देना चाहती है, सबसिडी देना चाहती है। लेकिन सिर्फ सबसिडी देने से तो विलेज इंडस्ट्री पनपने वाली है नहीं। यह तो अजीब सी बात है कि एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी मशीनरी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ विलेज इंडस्ट्री को भी बढ़ा रहे हैं। यह तो उस तरह की बात हुई कि घी को और अग्नि को साथ साथ रखें और घी को पिघलने न दें। यह कभी होने वाला नहीं है। अगर हमें विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, काटेज इंडस्ट्रीज का विकास करना है, तो बड़ी इंडस्ट्री को कहीं न कहीं हमें रोकना होगा। अगर नहीं रोकते तो किसी भी शक्ल में यह छोटी इंडस्ट्री पनपने वाली नहीं हैं।

[श्री चावदा]

प्लान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एक हमारे पास ऐसा साधन है कि जिस की वजह से आज हम हजारों गांवों में पहुंच सके हैं। भले ही कोई कहने को कह दे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट से या प्लान से देहातों में कोई फायदा नहीं होता, यह ग़लत बात है। हमें कबूल करना पड़ेगा कि उस से जरूर कुछ हद तक देहातों की हालत में, किसानों की माली हालत में फर्क पड़ा और अच्छा असर हुआ है। लेकिन हमें प्लानिंग के बारे में एक दृष्टि यह रखनी चाहिये कि जहां तक हो सके हमें उन प्रदेशो को भी लाभ देना है कि जो काफी पिछड़े हुये हैं। मैं अपने प्रदेश की बात कहूंगा। करीब पांच हजार चौरस मील का वह एरिया है और वहां उस पांच हजार चौरस मील के एरिया में एजुकेशन के परसेंटेज को हम देखें तो वहां पर तीन परसेंट एजूकेशन है।

हाई स्कूल सिर्फ दो हैं, अगर हम रास्ते बनाना चाहें और सीरियसली उन की जरूरत समझें तब तो १४०० मील के रास्ते वहां होने चाहियें। इस की जगह पर आज हमारे पास सिर्फ ५४ मील के रास्ते हैं। सब से बड़ी बात तो यह है, आप को सुन कर हैरानी होगी, दुनिया में हर चीज़ की चोरी होती है, लेकिन वहां पानी की भी चोरी होती है,। पानी की चोरी इस तरह होती है कि वहां हजारों चौरस मील के प्रदेश ऐसे हैं जहां पीने को पानी नहीं और वहां लोग गडढे वगैरह, जिन को आप तालाब कहते हैं, बना रखते हैं। बारिश में वह भर जाते हैं। बारिश में भर जाने के बाद लोग उसी में से लेकर पानी पीते हैं। उसी में से इन्सान भी पीते हैं और पशु भी जैसे बैल, घोड़े, गधे वगैरह, पीते हैं। उसी में कपड़े धोते हैं, उसी में नहाते हैं, उस पानी के पीने से लोगों को गिनी वर्म्स हो जाते हैं और यहां तक कि एक एक इन्सान में २५, २५, ३०, ३० गिनी वर्म्स हो जाते हैं। जबान पर होते हैं, आंखों पर होते हैं, यहां तक कि कई कई लोग तो जिन्दगी भर के लिये अपंग हो जाते हैं। ऐसी ऐसी जगहें हैं।

जहां तक मैं समझता हूं, हमारे प्लान बनाने वालों को और जो इस के लिये जिम्मेदार हैं, उन्हें अपनी दृष्टि में यह रखना चाहिये कि जहां पहले विकास की जरूरत हो, मैं तो विकास भी नहीं चाहता, आप हमें पीने को पानी दीजिये और नहाने धोने की पानी दीजिये, अगर आप इतना भी कर दें तो काफी है, तो जो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि जीवन की पहली जरूरियात भी नहीं पूरी हो सकती, उनको आप पहले हाथ में लें और वहां के लिये जहां तक जल्दी हो सके, पानी का इन्तजाम करें।

अब मैं कुछ थोड़ा सा टैक्सेज के बारे में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार, दो बार मैंने घंटी बजाई। अब बहुत हो चुका। Shri Sarangadhar Das. Not in the House. Shri B. S. Murty.

Shri B. S. Murthy (Eluru): Sir, I thank you for having given me an opportunity to speak on the Budget which has been very ably presented by our Finance Minister. The Budget is something like the outcome of a Rip Van Winkle. We have been given a plan. As usual, our plan began with a predetermined objective of raising the standard of living of the people of India. In accordance with this predetermined objective this is the fourth Budget our Finance Minister, a scholar and a philosopher.....

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): He has not claimed to be.

Shri B. S. Murthy:.....has presented to us.

I do not want to call this Budget as unimaginative. In fact this Budget suffers from over-imagination. But at the same time I must say that the fundamental problems confronting the country today have not been appreciated by the Finance Minister.

Before I come to these fundamental problems, I would like to give a warning to the ruling party. The party has been in power for nearly seven years in the Centre and it so happened that at the time of the presentation of the Central Budget there were two States in which elections were taking place, one in the South and the other in the North. In the South the Congress has failed; in the North the Congress has gained.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): We have maintained the *status quo*.

Shri B. S. Murthy: The hon. Minister for Parliamentary Affairs says they have maintained *status quo*. Well, *status quo* according to Malthus is a decaying process and the decaying process should be arrested if the party wants to stay for some time more. I am not saying this in disparagement. I want the Congress to be abreast of facts. In the South the intellegentsia has voted the Congress out; in the North the capitalists have mobilised behind the Congress. Another notable fact is that in the South the women have voted the Congress out. In Kerala the intelligent voters of the fair sex have voted the Congress out.

Shri Algu Rai Shastri (Azamgarh Distt.—East *cum* Ballia Distt.—West.): They are likely to become homeless!

Shri B. S. Murthy: That shows that the domestic front is rather precarious for the Congress. What I wanted to tell the Congress is that their proposals are not being accepted by the masses as they are. Therefore, there must be a reorientation in presenting the projects and plans. This was the thing which I wanted to say when I said about Kerala and PEPSU—nothing more or nothing less. It is for the Government to see whether there is any writing on the wall in the results of the two elections and to reassess their values, their projects and plans.

This Budget is not only not progressive but it is regressive; especially when the Minister of Finance has taken recourse to deficit financing for as much as Rs. 250 crores, I do not understand why he has thought it advisable to tax the poorer sections of the people. He has taxed footwear, taxed soap and taxed betel-nut. Especially in the South, betel-nut—I should say for the edification of the Finance Minister—is an apology for food.....

Dr. Lanka Sundaram (Visakhapatnam): Substitute.

Shri B. S. Murthy: It is an apology for food, I want to tell the Finance Minister and the House also. The worker when he is not able to get a morsel of food because of lack of money with him, goes to the nearest shop and spends a couple of pice and gets some betel-nut and betel-leaves and he goes on chewing it thinking that he has been munching some food and this is the appalling state of poverty in which the South Indian worker is found today.

This reminds me of a poem which, I think, has been written by Mary Lamb wherein she said that a poor and hungry boy not having food for two or three days went to a sweetmeat shop and saw the sweetmeats there for a number of hours and satisfied himself that at least he saw something there though he was not able to eat it. In the same way, the worker in the South has to take this betel-nut as an apology for food because he cannot get food. The Finance Minister has not provided work for him. Unless work is given, there is no earning; if there is no earning there is no purchasing power and if there is no purchasing power there is no food—this

[Shri B. S. Murthy]

is the vicious circle in which our present rulers are keeping the masses in India.

The Minister of Finance (Shri C. D. Deshmukh): We can grow more betelnuts.

Shri B. S. Murthy: The Finance Minister's suggestion will help him to get more revenue but not in giving more nut for the worker.

About soap, I think I better leave it to the Industry Minister who has made a thorough study of it, to see whether it will yield anything or not without hitting the smaller fry in the industry. About footwear it is again the consumer who has to pay the tax. All the taxes the Finance Minister has brought in are taxing only the consumers and also the lower strata of the community. Therefore, I think that when they are taking recourse to deficit financing to the extent of Rs. 250 crores they could also forgo this and leave it to the future how to manage it.

About this deficit financing I must say a word. The Minister has not been able to explain to us the result of the deficit financing. So far as employment is concerned, according to the figures supplied on the floor of this House recently, it looks as if nearly 20,000 people per month—mostly skilled labourers—are coming to the employment exchanges and registering themselves. I do not know how far the Finance Minister with his Plan and the Budget will be able to give employment for these people who are trying to eke out their daily bred. In this connection I must say that the two fundamental problems confronting the country today are poverty and unemployment. If you go to the rural areas you will see that poverty in all its nakedness is having its sway. There are people today who are not having even one square meal a day. What is the use of telling these people wait for some time more, the Plan will fructify in God's good time and then you will get food? Today, after all, food is the prime concern, though it is stated that bread is not the only question. We know

बिन भोजन के भगवान कहां।

If there is no food there is no God and if there is no food there cannot be any government also. Government has to think seriously about this problem. The poorer classes, the landless labour, the toilers and the moilers of the country are not having anything. Therefore there must be a proper appreciation of the problem. Unemployment is the source of all evils. You know why there is more and more uprising in the country, not in the revolutionary sense; but after all they must ask, and they are asking you to give food. But you are telling them: wait, take this Plan, read it and digest it and it is food for you. I think it is high time that the Finance Minister came with concrete plans to obliterate poverty as well as unemployment in country.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member wants the Minister to give food without a plan.

Shri Nambiar (Mayuram): If possible.

Shri B. S. Murthy: The child asks for food. It is for the mother to go on with the plan or the project.

Because you have given me only one minute more I want to say something about Community Projects. Community Projects are welcome. But today I am araid most of these Community Projects are being manned by persons having antediluvian ideas. They are people who do not have any progressive ideas. They think they have got it because of their past service to the country by belonging to a certain party. These people must be soon replaced and young and energetic blood must be brought into the field. We should see that they make full use of the help we are getting from other countries. It is no use putting persons there who have no progressive ideas. who have reached the maximum of the

progress that they could ever make. I want to see that the Community Projects give as much help to these rural areas as possible. That is only possible if they are manned by persons with a better outlook than most of the people who are manning them today.

The Parliamentary Secretary to the Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): This is the fourth day of discussion of the fourth budget of the Finance Minister. It is really very heartening that both in the House as well as in the country there has been a very large measure of support and appreciation of this Budget. I should like, with your permission, Sir, to intervene at this stage and clear up a few factual points arising out of the discussion in these four days.

Before I go to other points I cannot but refer to the paradoxical manner in which Mr. H. N. Mukerjee has propounded his thesis about increased employment and increased production and some other matters. He has found very serious defects in the Budget and he said that this is the worst budget of all the four budgets of the Finance Minister. And still he says that he likes him. I cannot but recall to this House the meaning of the famous poem, which I cannot forget, of the great Hindi poet Surdas, where he describes the divine espouse Radha as finding fault with Lord Krishna in his mischief and everything, and still liking him or loving him.

Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur): Will the hon. Member quote that poem?

Shri B. R. Bhagat: I am sorry, it is not with me just now.

Shri Nambiar: He did not like it—he disliked.

Mr. Deputy-Speaker: Sometimes speeches become romantic.

Shri B. R. Bhagat: With these remarks I cannot but point in a very surprising manner to the statement made by my hon. friend Shri V. G. Deshpande, where he has charged the Government that it is not doing everything possible to rehabilitate the refugees. It is good to make politics out of it, but I must point out that it is not fair for an hon. Member to make incorrect statements. I heard his speech and just to check up, I also went through the official report. He says that a sum of Rs. 4 crores has been provided for the rehabilitation of refugees, and according to him he has rightly charged the Government for neglecting the cause of the refugees. I would request him, Sir, through you, to just read a bit more carefully the budget papers. A sum of Rs. 34·32 crores distributed over a number of demands has been clearly earmarked for Rehabilitation, including about a little over 10 crores on the revenue account and over 23 crores on the capital account. The mistake that he has made is that, capital budget for Rehabilitation includes a some of Rs. 4 crores for compensation to the refuges, and this amount has been taken by him as the total amount allotted for the rehabilitation of refugees this year.

Shri V. G. Deshpande (Guna): What I said was that only a sum of Rs. 4 crores was being alloted towards compensation to refugees, and that more should have been allotted.

Shri B. R. Bhagat: I may inform the House in this connection,—as he has laid this charge at our doors,—that up till now the total amount spent on rehabilitation (including this year), is to the tune of Rs. 205 crores, and I think the greatest chit of appreciation that this Government can get is that it has been able to solve the problem of refugees in the best manner possible. I feel that there are items on which some more progress has to be made, but the work so far done has been quite appreciable.

I would now refer to another point raised by my hon. friend Shri S. N. Das. He complained that there has been inordinate delay in the rural credit survey, and charged Government for treating the rural areas, their prosperity and the credit which is so much needed, with half-heartedness. This has been the subject of several interpellations in the House and therefore, the House owes an explanation from

[Shri B. R. Bhagat]

the Government. I think there has been no undue delay in the Publications of the report. This has been rather an unusual type of survey covering some six hundred selected villages all over the country spread over seventy-five districts. An enormous amount of material has been collected which has to be compiled and conclusions drawn so that this very important aspect of the rural credit may be examined and definite conclusions arrived at. Sir, the matter is in the drafting stage and, I think, before long this report will be out.

The third point which the hon. Members referred to is that the provision of Rs. 48 crores made in the Budget by way of foreign assistance is not called for in the present international situation and that there may be a shortfall to that extent as this amount may not be coming at all. If we go into the details, we will find that it is wrong to come to this conclusion because all the amounts budgeted are authorised ones. We have entered into agreements as regards supply of equipment and other things and there is no uncertainty about them. This amount consists of Rs. 3 crores from the International Bank for Reconstruction and Development. From U.S.A. 20 million dollars for the supply of locomotives 25·5 million dollars for the supply of iron and steel and lastly Rs. 4 crores for irrigation and hydro-electrical equipment from Canada and Australia have been provided for. In all these cases, we have entered into agreements and supplies will be coming in the course of the year. There is nothing uncertain about it. We have not taken into account any uncertain element in this Budget so far as foreign assistance is concerned.

Coming to the more important points referred to by Shri H. N. Mukerjee and Shrimati Sucheta Kirpalani, I should like to say something. Shrimati Sucheta Kripalani has said that the increase in industrial production that has taken place must be attributed to fuller utilisation of existing capacity and not to investment. I agree that a great part of the improvement in industrial production has been due to the better utilisation of the capacity which had hitherto been idle. But, we should not, on the other hand, forget that there have also been increases in the installed capacity in several industries such as cement, rayaon, paper, electric lamps, bicycles, electric fans, radio receivers, sewing machines, tea chests, caustic soda, sheet glass and certain types of textile machinery. The fact that big Government enterprises like Sindri and Chittaranjan have gone into production cannot also be dismissed as of no significance. Even though we grant that there has been increased production due to the greater and fuller utilisation of the idle capacity, what is the inference that we should draw from this? No one can say that the industrial progress of this country has been at a fast enough rate. No one can deny that what we want is more investment. It is in this context precisely that the Finance Minister has formulated the Budget proposals. Resort to deficit financing means that we are very particular about investment for economic development. Unless there is more investment, more production, more income and more employment, and this cycle goes on, there is no way out of the present economic crisis.

The Indian economy is now in a much better shape than it was a couple of years ago. Food production has gone up. So has our industrial production. Our foreign exchange resources are such that we can afford a little more of necessary imports. Prices have come down. Inflationary pressure has disappeared. This, I agree, is no prosperity. But, I do not know why hon. Members should say that it is false prosperity. We did not claim it. Of course, as the Finance Minister said in his speech, the picture is changing. Do not these factors indicate that the economic picture is changing?

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Changing for what?

Shri B. R. Bhagat: For the better. It will take many years of hard work before the word "prosperity" can be used in the Indian economic context. Nevertheless the fact remains that production has improved. Utilisation of idle capacity is the first step in that direction. This accords with the recommendation of the Planning Commission. It has been possible to utilise idle capacity because, if I may put it briefly, thanks to the Plan and to some extent to Nature's bounty, the shortage of food and raw materials consequent on the war and partition have been made good.

I will then refer to the paradox, raised by my hon. friend Shri H. N. Mukerjee, of increased production and increased unemployment. He is a very keen student and has a very keen mind. Yet, I do not know if he has tried to grasp the economy of backward countries. Not only in India, but in all backward countries where there is a heavy dose of population, this phenomenon occurs. The factors making for the worsening of the unemployment situation since about the middle of last year have been gone into several times in this hon. House. Firstly, we do not quite know whether unemployment in the country as a whole has increased. We have figures relating to a small sector which indicate a worsening of the situation. There are reasons on the other hand to believe that employment in organised industries has been well maintained. As developmental expenditure under the Plan goes up, employment opportunities do not expand at a rate rapid try in which population is increasing rapidly, employment as well as unemployment can increase simultaneously, if employment opportunities do not expand at a enough to absorb new entrants. This is the situation that obtains in the country. But what is the remedy? How is this paradox to be solved?

The paradox arises from the fact that several industrial units have been carrying a labour force larger than is strictly necessary, and new investment has been hampered by the sudden change in world conditions from a sellers to a buyer's market. This transitional phase, we hope, will soon be over. It obtains in many other countries on this side of the hemisphere. But I agree that our major problem is to increase production as well as employment. These are the two sides of the same medal. If there is increased production without employment, it will lead to a decrease in the purchasing power and production will get a setback. If there is increased employment and purchasing power without increasing production, it will develop shortages and inflation. My reply to my two hon. friends is that what we now want is to build up increase in production and to resolve this paradox.

I will refer, lastly, to another point made by my hon. friend Shri H. N. Mukerjee. He charged the Government with not tapping the untapped resources by way of profits, both Indian and foreign. Let us examine the Indian case he has cited. He wants us to fix a ceiling on profits. Attractive though this might sound to those who want to eliminate private enterprise altogether, the practical question is whether profits in industry at present are too high, whether the country at present is faced with what in economic terminology is called "a profit inflation". There are no signs of this. At least my hon. friend has not given any evidence or proof of this—that there is a "a profit inflation" in this country and therefore there must be some ceiling fixed on profits.

He has referred to an article in the *Free Press Journal* which I carefully read after hearing his speech, which gives the results of a study of the profits of 79 companies. This article says that on a paid-up capital of Rs. 83 crores, these companies made a net profit of Rs. 15 crores. But if one were to take into account the reserves

[Shri B. R. Bhagat]

of Rs. 68 crores, the net profit works out to about ten per cent. The article itself points out that the dividends paid out by these companies amounted to Rs. 8 crores, which gives a return of six per cent. on the paid-up capital and reserves, which is not very unreasonable. I am afraid there is some confusion in the mind of the hon. Member, and he seems to think that the reserves of Rs. 68 crores were earned in 1952-53. This, of course, is not true. He expressed in another context the need for ploughing back profits. So, I do not see why he objects to the reserves which have been built up over a period, which will ultimately go to investment.

There is, I am afraid, a similar misunderstanding in regard to the foreign remittances, to which he has made a reference. I must frankly confess that there is something wrong in the Communist Party's Research Bureau, because I went through the proceedings of the Council of States, and there also, I found that a similar misconception had arisen. He has spoken of profit remittance to the tune of Rs. 200 crores by the foreign companies, while some of his colleagues in the other House have referred to a profit remittance of about Rs. 130 crores. We would like to know from the hon. Member where he gets his figures from and what the method of arriving at these estimates is. We have an authoritative study by the Reserve Bank of India on this subject, on the basis of which, the estimate comes to Rs. 39 crores only. There is not, therefore, any vast scope for taxation here, as the hon. Member has pointed out.

Further, to stop remittance of profit is to stop the inflow of foreign capital. Our policy in this respect has been enunciated in clear terms, and certain assurances of reasonable returns to foreign investors have been given by Government. India needs foreign capital on terms which we consider fair to both parties, and there is no evidence yet that this policy needs to be changed.

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जब मैंने विचार करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि हम महज अच्छाइयां देखें या सिर्फ इस पार्लियामेंट की तमाम चीजों को डिसपैशनेट तरीके से, बिल्कुल एक सही तरीके से देखना चाहिये। हमें इस नक्शे पर ध्यान देना चाहिये जो आर्थिक नक्शा बजट में पेश किया गया है।

इसमें शक नहीं कि पिछले पांच छःसालों में जिस तरह से हमारे फाइनेंस विभाग को चलाया गया है और जिस तरह से हमारी इकानमी को चलाया गया है उससे हमारी इकानमी के अन्दर स्थिरता आई है। इस चीज से इन्कार करना और यह कहना कि हमारे देश का आर्थिक ढांचा मजबूत नहीं हुआ है गलत होगा और ऐसा कहने से जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको इस क्रेडिट से वंचित करना होगा जो कि उनका ड्यू है। जो हमने प्लान्ड इकानमी बनाई है और जो प्लानिंग वगैरह किया है उसके लिये यह कह देना कि इससे कोई तरक्की नहीं हो रही है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं होगा। हम यह कह सकते हैं कि प्लानिंग का जो दायरा है वह संकुचित है, लेकिन यह कहना कि संकुचित दायरे के अन्दर भी जो प्लानिंग किया गया है वह बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। मैं और सूबों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं पंजाब के बारे में कह सकता हूं जो लोग पंजाब में जाते हैं वे कह सकते हैं कि इस पंच साला प्लान से हमारे सूबे में तरक्की हो रही है। अगर कोई आदमी बिल्कुल आंखें बन्द नहीं कर लेगा तो वह नहीं कह सकता कि वहां तबदीली नहीं हो रही और नहरें और बिजली

जो कि वहां मुहैय्या की जा रही हैं उनसे तरक्की नहीं हो रही है उससे हमारी इकानमी नहीं बदल रही है और वहां के लोगों के दिलों में यह खयाल नहीं पैदा हो रहा है कि पंजाब की आर्थिक हालत संभलने वाली है। अभी जो काम हो रहा है उसमें देहातों में बिजली देने का और छोटी इंडस्ट्रीज को बिजली देने का काम हो रहा है। कुछ देहातों में बिजली जा चुकी है और अभी तीन सौ देहातों में और बिजली देने का प्रोग्राम है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वहां पर छोटी छोटी दस्तकारियों के लिये बिजली दी जाये। यह सब चीजें हमारे सामने हैं। इसी तरह से और काम भी हो रहा है। मैं नहीं कह सकता कि और प्रान्तों में क्या हालत है लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो प्लान बनाई गई है उसकी रहबरी में पंजाब की इकानमी उन्नति कर रही है और उस में काफी तरक्की ही रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह अनुभव करता हूं कि इन तमाम चीजों के होते हुये भी जिस तेजी के साथ हमें तरक्की करनी चाहिये और जिस तेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिये उस तेजी के साथ हम नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी इकानमी में जगह जगह कुछ ऐसी रुकावटें हैं कि जिससे हमारी तरक्की तेजी से नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि वह रुकावटें इतनी फिजीकल नहीं हैं जितनी कि दिमागी है। हमारा दिमाग इस बात में अभी साफ नहीं है कि हमें किधर आगे बढ़ना चाहिये हम अभी तक यह तय नहीं कर सके हैं कि हम को बड़ी इंडस्ट्रीज को अपनाना चाहिये कि या छोटी इंडस्ट्रीज को अपनाना चाहिये और अगर दोनों को अपनाना चाहिये तो किस अनुपात में हम छोटी इंडस्ट्रीज को अपनायें और किस अनुपात में बड़ी इंडस्ट्रीज को अपनायें। प्राइवेट और पबलिक सेक्टर को मिला कर हमने एक मिक्स्ड इकानमी जरूर स्वीकार की है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या दरजा होना चाहिये और पबलिक सेक्टर का क्या दरजा होना चाहिये यह बात साफ नहीं है। हमने टक्सों से और दूसरे जरियों से रुपया इकट्ठा किया और डेफिसिट फानेनसिंग भी किया और काफी रुपये का प्रबन्ध किया, लेकिन हम इस बात को ठीक से तय नहीं कर पाये है कि इस रुपये को कहां किधर और कैसे लगाया जाये। कभी हम इसमें से कुछ रुपया प्राइवेट सेक्टर में फेंक देते हैं और कभी पबलिक सेक्टर में फेंक देते है। हमारा आर्थिक ढांचा क्या हो और किस दिशा में हम तरक्की करें इस बात को हम नहीं समझे हैं और इसी वजह से हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमको उस वक्त तक प्लानिंग का फायदा नहीं मिल सकता जब तक कि हमारा दिमाग इन मामलों में साफ न हो कि हमें किधर बढ़ना है। हमको बतलाया गया है कि हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कुछ गिर गया है, और उसकी प्राइस गिर गई है क्योंकि बाहर की मंडियों में डिमांड नहीं है। हमारा प्रोडक्शन मुख्य तौर पर एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर हमारा प्रोडक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर हमारी एक्सपोर्ट हो तो हमारा प्रोडक्शन बढ़े और अगर एक्सपोर्ट न हो तो प्रोडक्शन घट जाय और हमारे यहां बेकारी बढ़े तो हम नहीं बढ़ सकेंगे और हम कमजोर रहेंगे। हमें अपने प्रोडक्शन के लिये महज दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इसके अलावा जो हमारा राजनैतिक दृष्टि से "फ्रेंडली एरिया' है उसको हमें 'इकानमीकली फ्रेंडली एरिया' भी बनाना चाहिये। लेकिन हमारी तमाम इकानमी और हमारा तमाम प्रोडक्शन अन्दरूनी कंजम्शन पर निर्भर रहना चाहिये ताकि अगर बारह का एक्सपोर्ट कम हो तो हमारे यहां बेकारी न फैल जाय और प्रोडक्शन कम न हो जाय। हम जितने ज्यादा अपने अन्दरूनी कंजम्शन पर निर्भर रहेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इकानमी मजबूत होगी। मैं यह अनु-

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

मव करता हूं कि इस बात में भी हमें अपना दिमाग साफ करना चाहिये कि हम किन किन चीजों का प्रोडक्शन करें और कहां कहां रुपया लगायें और कितना रुपया लगावें और किन चीजों को बाहर भेजने के लिये बनावें। इन चीजों में हमारा दिमाग साफ होना चाहिये जो कि अभी नहीं है।

जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसके चौथे पेज पर बेकारी के मुताल्लिक जिक्र किया गया है। बजट में बतलाया गया है कि एक साल में बेकारों की संख्या एक लाख बढ़ गई है। यह फीगर एम्पलायमेंट एक्सचेंज से लिये गये हैं।* बेकारी बढ़ रही है इस चीज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन अपनी बजट स्पीच में अर्थ मंत्री साहब ने यह कहा कि यह तो एक ऐसा मामला है कि इसको जल्दी हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है :

"Unemployment is not a short term phenomenon calling for short term remedies".

4 P.M.

उनका ख्याल है कि यह तो बहुत लम्बी चीज है और यह बेकारी थोड़े अरसे के अन्दर दूर नहीं हो सकती, इसमें काफी अरसा लगेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि बेकारी का पूरा इलाज तो जल्दी नहीं हो सकता। इसके लिये कोई शार्ट टर्म रैमिडी नहीं ही सकती, अगर इसको हमें मुकम्मिल तौर पर दूर करना है। आपने आखिर में सिर्फ कह दिया कि हमारी प्लानिंग के बाद इसके लिये काफी गुंजाइश है कि बेकारी दूर हो जायेगी और इस बात के लिये प्लानिंग में काफी उपाय सुझाये गये हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरे ऊपर यह असर पड़ा है कि बेकारी की समस्या एक ऐसा मसला है कि इसके लिये तुरन्त हम कुछ नहीं कर सकते। बस इन्तजार कीजिये। मगर यह सब गलत है। यह मैं मानता हूं कि हम कतई तौर पर बेकारी को तुरन्त दूर नहीं कर सकते, आखिर में प्लान में कुछ उपाय सुझाये गये हैं और समय पाकर यह दूर होगी। लेकिन आपको तुरन्त भी तो कुछ उपाय करना है। आप उन से पूछिये जो बेकार हैं, जो इस बेकारी के शिकार हैं, जो खाने को रोटी चाहते हैं। वह फौरन काम चाहते हैं और इन लम्बी चौड़ी स्कीमों से उनका पेट नहीं भर सकता, उनके दिल को संतोष नहीं होता। इसीलिये हमको कोई ऐसे उपाय ढूंढने चाहिये कि जिन से हम इस बेकारी की समस्या को तुरन्त कोई हल कर सकें। चाहे वे उपाय अस्थायी हों। जिससे यह समस्या कुछ हद तक हल हो सके। आपने बजट स्पीच में इसके लिये कोई उपाय नहीं बताये और बजट की स्पीच को पढ़ने के बाद कुछ ऐसा आभास हुआ कि उस समस्या को जो महत्व आपको देना चाहिये वह आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह कह कर टाल दिया है कि इस लम्बी चीज के लिये लम्बी रैमिडी की जरूरत है।

जो नये टैक्स लगाये गये उन के सम्बन्ध में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह जो नये टैक्स हैं वे कन्ज्यूमर गुड्स पर हैं, ऐसे लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर हैं कि जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन पर, जूते पर टैक्स है और आर्टीफिशियल सिल्क पर टैक्स है। रेशम पर जो टैक्स है उसके लिये आप यह कह सकते हैं कि वह लग्जरी है। लेकिन वह पूअर मैन्स लग्जरी है, गरीब लोग जो अच्छा रेशम नहीं पहन सकते शौक को पूरा कर लेते हैं। हमारा टैग्जेशन का जो स्ट्रक्चर है, उस पर विचार हो रहा है, कमीशन बैठा है। लेकिन अभी ही आपने जो टैक्स बढ़ाने का निर्णय किया तो सोचना चाहिये था कि आम लोगों की, गरीब लोगों की इस्ते-

माल की चीजें हैं उन पर टैक्स ज्यादा न लगायें मैं बाकी प्रान्तों की बात तो नहीं जानता, लेकिन लुधियाने और अमृतसर के एरिया में कई कारखाने इस आर्ट सिल्क के कपड़े के हैं। आपको इस बात से खुशी होनी चाहिये कि वहां पर शरणार्थी लोगों ने तथा दूसरे व्यापारियों नें इस बात की परवाह न करते हुये कि अमृतसर सीमा प्रदेश है, विभाजन के पश्चात् करीब एक करोड़ रुपया इन कारखानों के अन्दर लगाया है। पहले भी कारखाने थे, लेकिन विभाजन के बाद एक करोड़ रुपया लगा है और उससे काफी रिफ्यूजीज को शरणार्थियों को, वहां काम मिल रहा है। इस टैक्स के लगने से काफी लोग वहां बेकार हो रहे हैं। जो वहां छोटे छोटे सरमाये के लोग हैं वे इस टैक्स को बरदाश्त नहीं कर सकते। मेरा सम्बन्ध वहां की लेबर यूनियन्स से है और वहां का अनुभव रखता हूं। वहां के एम्लायर्स के रवैये से मुझे शिकायत रहती है। लेकिन मैं इस बारे में अनुभव करता हूं कि एम्पलायर्स और मजदूरों दोनों के हित का ही मसला है, दोनों का ही सवाल है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बात को आपके सामने रखूं कि आर्ट सिल्क के बारे में कुछ काम करना चाहिये, और आपको टैक्स लगाना ही है तो बीस या पच्चीस लूम्स, इस तरह की कोई लिमिट, हद, मुकर्रर करनी चाहिये कि जिनके ऊपर यह टैक्स न लगे। यह सब आपको देखना चाहिये।

इसके साथ साथ मुझे कुछ सरकारी खर्चे के मुताल्लिक भी कहना है। इस वक्त सरकार का जो इन्तजाम है वह बहुत खर्चीला है। तमाम देश में इस बात को अनुभव किया जा रहा है और खर्चा कम करने के लिये काफी प्रस्ताव होते हैं। पता नहीं कि उनके बारे में आपके आफिस में क्या किया जाता है। एक बात मुझे मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट

ने खर्चा कम करने के लिये एक प्रस्ताव रखा कि ७५० रुपये से ऊपर जो लोग तनख्वाह पाते हैं उन के मंहगाई अलाउन्स को कट कर दिया जाय, लेकिन गवर्नमट आफ इंडिया ने उसमें रुकावट पैदा कर दी और पंजाब गवर्नमेंट यह कटौती न कर सकी। गवर्नमेंट आफ इंडिया के रुकावट डालने से अब तक पंजाब गवर्नमट यह कमी न कर सकी। इस बात की पंजाब गवर्नमेंट ने शिकायत भी की है। मैं समझता हूं कि यह एक तरह से पीछे डालने वाली बात है, एक रीएक्शनरी स्टैप है। चाहिये तो यह था कि इस तरह के काम में गवर्नमेंट आफ इंडिया दूसरों को रास्ता दिखाती प्रगति की ओर ले जाती, मैं यह महसूस करता हूं कि इस सरकार की तरफ से ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिये।

इसी तरह से जो अभी तनख्वाहों में गैप है, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले और कम से कम तनख्वाह लेने वालों के बीच का जो अन्तर है, उसको भी कम करना है। वह प्रयत्न भी अभी तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से नहीं हुआ। बजट की सारी स्पीच में उस तरफ कोई ध्यान दिया गया नहीं मालूम होता। यह नहीं मालूम होता कि उस तरफ कोई विचार किया गया है या नहीं, या फाइनैन्स मिनिस्टर साहब उस तरफ सोच भी रहे हैं या नहीं।

भारत सरकार के दफ्तरों में भी काफी शिकायतें हैं, जैसे कि छोटे मुलाजिमों की सरविस कंडीशन्स को उन्नत करने की बात ह, इस बारे में कुछ नहीं किया गया। इसी तरह सिलक्शन और प्रमोशन के बारे में काफी झगड़ा रहता है। छोटे मुलाजिमों की हाउसिंग की प्राबलैम है, उनको मकान रहने को नहीं मिल पाते। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

रूल्स भी एक तरह से नहीं है, अफसर के दिल में जो आता हैं वैसे ही वह करता है, समता नहीं है। तो इस तरफ भी कुछ होना चाहिये।

सब से आखिर में मैं एक बात और कह कर खत्म करता हूं। भ्रष्टाचार की काफी शिकायत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की टोन ऊंची नहीं होती। हमें चाहिये कि देश में ईमानदारी के साथ काम करने की, देश के लिये काम करने की प्रवृत्ति हो, यह अभी नहीं है। हमें चाहिये कि हमारे मुलाजिमों में कर्तव्य पालन की स्वेच्छा से और निस्वार्थ भाव से प्रवृत्ति हो। इस तरफ अभी तवज्जह नहीं दी गई है। इसके लिये गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारे नेता लोग हैं उनकी तरफ से कोशिश नहीं हो रही है कि वह ऐसी भावना लोगों में पैदा कर दें, ऐसा वायुमंडल पैदा कर दें कि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की टोन ऊंची हो जाय। मैं इस बात को लम्बी नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के लिये विशेष प्रयत्न करने चाहिये कि जनरल टोन ऊंची हो और भ्रष्टाचार की कमी हो।

एक शिकायत मैं एजूकेशन डिपार्टमेंट से करना चाहता हूं। यहां केम्प कालेज बहुत दिनों से है और उसमें बहुत से पंजाब के शरणार्थी भाई हैं, उनकी कोशिश से यह केम्प कालेज बना है। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट उसको बन्द करने वाली है। यह ठीक है कि इसके अन्दर कुछ टक्निकल वजूहात हैं कि यहां दिल्ली यूनीवर्सिटी है। लेकिन यह सब होते हुये भी इसके लिये कोई मार्ग निकालना चाहिये यहां दिल्ली में बहुत कम शिक्षणालय हैं। शिक्षणालयों की संख्या इतनी कम है कि सब विद्यार्थी आसानी से दाखिल नहीं हो सकते। यह एक शिक्षणालय बहुत सफलता से चल रहा ह, उसको जारी रखने से बहुत फायदा पहुंच रहा ह, इस दृष्टि से उसको कायम रखना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देगा और टेक्निकल बातों को बीच में डाल कर उसको बन्द करने की कोशिश नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

Shri G. D. Somani (Nagaur-Pali): I would like to congratulate the hon. Finance Minister on his presenting a bold development budget this year. The hon. Finance Minister had promised more than once in the past that he would not allow the development programme of the country to suffer due to lack of resources, and we find that he has shown the Government's determination to get the necessary resources for the implementation of the Five Year Plan, whether it has been by additional taxation, by borrowings, by foreign aid, or in the last resort, by recourse to deficit financing subject to certain safeguards. I do not share the pessimism of those members who say that there is a dark economic situation today. I do feel that the policies of the Government of India during the last few years have been able to restore confidence and stability in our economic situation and to control the inflation, a fact which has also been recognised by the report of the Mission of the International Monetary Fund which was released recently. Strong objection was taken by one or two Members to the remarks of the hon. Finance Minister that the face of the country is changing, and is changing for the better. I am painfully aware of the fact that our standard of living is among the lowest in the world, and

poverty and unemployment are rampant throughout the country, but still, if one visualises and sees the process of developments in which the Government are engaged at present, —in the construction of huge river valley multi-purpose projects, the community projects operating in the rural areas and several other projects of important development,—one cannot fail to realise the picture of a new India that is steadily emerging by the efforts of the Government. It may not be possible to clearly assess the effect of these projects just at present, but those who can visualise the effect when all these huge projects are put into operation can certainly see that the remarks of the Finance Minister are not unjustified.

Doubts and fears have also been expressed about the magnitude of deficit financing. I for one would like to say that if the choice is given between deficit financing with certain safeguards on the one hand and the curtailment of our development programme on the other. I would certainly advocate the former course. The Finance Minister has already promised to keep a close watch on any inflationary pressure that may arise in this deficit financing, and I have no doubt that a policy of liberalising imports and intensifying the borrowing programme will be followed vigorously to neutralise the effects of deficit financing to a considerable extent. I would, however, like to say a few words about the administrative machinery which both the Centre and the States have got at their disposal to cope with the huge development programme. We find that the Government of India are committed to a huge expenditure of something like Rs. 1,200 crores in the next two years of the Plan. Looking through the records of progress made in the last three years, it seems, however, extremely difficult that the Government will be able to realise this target. The Finance Minister has, of course, indicated, in the course of his speech, certain special measures that are being taken to push forward the progress of the Plan in the remaining period, but it is extremely doubtful, without very exceptional and special measures, whether the Government will be able tc achieve the targets of the Plan and will be able to usefully spend this huge amount of Rs. 1,200 crores during the next two years. Another important point also arises in this connection, and that is whether the Government are satisfied that the normal checks and supervision that they have for the expenditure on this huge programme will be sufficient to ensure that every pie that is spent will be utilised properly and usefully. During the past when the Government had a development programme of a far less magnitude, we are aware of several instances where irregularities have been committed and where there has been considerable wastage of public money. I have no intention to cast any general reflection upon the administrative machinery, but things, as they are, have got to be faced, and I would submit respectfully that the Finance Minister should not be satisfied with his routine checks for ensuring that this huge amount of money will be utilised properly. In this connection, suggestions have been made in the House for the appointment of a Parliamentary committee.

I would go even further and say that as we have got Members of Parliament, the members of the various State legislatures, business people of proved integrity and experience and also other public men, there is no reason why the Finance Minister should not utilise the services of these people in constituting small committees associated with each huge project or each huge spending department of every State for the purpose of ensuring that a close scrutiny and watch will be kept on the spending of the huge amount that is envisaged in the Plan. I would

[Shri G. D. Somani]

like to say most emphatically that no useful purpose will be served by holding a *post-mortem* enquiry later. Our experience in the past does clearly indicate that the Finance Minister should not be satisfied with his usual, routine, administrative checks for the execution of the programme, but he must consider the constitution of some sort of a committee that will keep a close watch to ensure that the amount is utilised properly and usefully.

Having said so much about the public sector, I would like to make a few observations about the private sector. I would not like to say much about the taxation policy of the Government since the Finance Minister has already declared that he is not going to make any major change pending the recommendations of the Taxation Enquiry Commission. I would only like to endorse what my friend, Shri Tulsidas Kilachand said in this connection, and I hope the observations he made will receive proper attention, by the Finance Minister. I would, however, like to draw his attention to an important feature of the Government's policy which adversely affects capital formation and development of several industries, that is the policy of fixing control prices on a basis which leaves very little margin for the shareholders and investors. Sir, I may refer to two instances, steel and cement, where in spite of the clear recommendations of such a scientific and impartial body as the Tariff Commission, the Government of India did not see their way to fix the prices on a basis of 10 per cent instead of 8 per cent as they did. Sir, this 8 per cent even is subject to taxation, subject to bonus for labour, subject to managing agency commission, and in actual fact it comes to about 3½ per cent. May I ask, in all humility, whether the Finance Minister is satisfied that in the present context of circumstances, this 3½ per cent return for the holders of equity capital is justified, and whether the recommendations of such an impartial and scientific body like the Tariff Commission should be ignored in the way in which it has been done in the case of certain important industries like cement and steel? I have no quarrel with Government if they want to continue the control of prices of essential commodities, but when they do control, then certainly they must see that these industries do get a fair return on their investment, to enable them to plough back their profits for rehabilitation and expansion. My hon. friend Shri Bhagat just now himself declared that Government regards 6 per cent return to the shareholders as quite reasonable. I do not see how this 3½ per cent return policy in the case of cement and steel can be justified in view of the present conditions of the money market.

I would now like to refer to the new taxation proposals which have been submitted. In this connection I will take up first the excise duty on cotton textiles. I am not opposed, in principle, to the excise duties, but the manner in which these excise duties on cotton textiles have been changed and adjusted not only from year to year but even twice a year, really does indicate that there is something not quite satisfactory with the machinery which is dealing with these excise duties. What happened last year? The Government of India increased the excise duty on fine cloth, especially in lower varieties, by something like one hundred per cent. Representations were made by the industry; I also more than once pointed out in this House that it is bound to affect the production of fine varieties, and also consumption of foreign cotton, a factor which should have been foreseen by Government themselves at that time. However, the hon. the Finance Minister did not choose to heed the representations made by those who knew something about the industry. The result

was that there was a steep decline in the production of fine varieties. I have got certain figures which show that the production of fine varieties fell from 4,46,923 bales in April-October 1952 to 3,28,662 bales in April-October 1953, which means that there was a decline of about 25 per cent. in these fine varieties. What happened? The realisation for Government from this excise duty in spite of the enhanced rate was more or less the same amount, but the position of Indian cotton was aggravated and Government were compelled to reverse their policy. They have had to take off the duty on imported cotton. At last they realised that the whole policy that was adopted last year has to be reversed.

My submission is this. We have in the Government a Textile Directorate working for the last ten years. It is really surprising that our officers who have been dealing with the textile question all these years should not have been able to assess the impact of the policy that they recommend to Government for being adopted. When injury is done to an industry it is difficult to undo it. It is, therefore, in the fitness of things that when Government takes recourse to more and more of excise duties, the machinery which they have at their disposal should be utilised to function efficiently. The difficulties should be foreseen ahead and action should not be taken only after the damage has been done.

Then, take the example of duties on art silk fabrics. This is not a major industry. I find almost 80 per cent. of factories manufacturing art silk fabrics consist of less than one hundred looms. This is a small-scale industry which cannot bear this duty. So unless something is done to readjust or take off this duty on art silk fabrics, it is absolutely clear that these small factories operating in different parts of the country will have to severely curtail their production and many of them may have to be closed. My submission in this connection is this: while these excise duties are proposed and levied, no proper study is made and no scientific data collected to see the incidence of the levy on the industry in particular and on the economic condition of the country in general. If an industry is not able to bear the burden, and remedial action is taken somewhat late, by that time injury, which cannot be repaired later, is done. So, when these excise duties are now forming an important source of revenue and the Finance Minister, as he said, is likely to take recourse to these duties more and more in future, I would again suggest that it is in the general interest of the country that before imposing any excise duties Government should have at their disposal all the facts and figures about the various industries which are affected by them, so that nothing is done to adversely affect the whole economic fabric of the country.

Sir, I would in the end like to welcome the proposals about setting up of two development corporations for the private sector. As I said in the beginning, Government have strained their resources to the utmost for finding funds to finance the public sector. But I do feel that Government have not shown the same urgency and the same promptness in finding resources for the private sector. We have been hearing about this State industrial development corporation for quite a long time. But the leisurely way in which the whole question is being tackled leaves much to be desired. The private sector, as you know, provides the largest scope for employment, if we leave the agricultural sector alone. It has been estimated that private sector gives employment to 75 to 80 per cent. of the non-agricultural population. Therefore any special facilities, or any resources made available to the private sector will go a long way in meeting the unemployment situation, the seriousness of which we all realise. I do hope and

[Shri G. D. Somani]

trust that these two development corporations will come into being in the near future and the Finance Minister will also see that steps are taken which will enable the private sector to get more and more resources, so that the development of the country both by the public sector and the private sector may go hand in hand.

Dr. Mathuram (Tiruchirapalli): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Before coming to the different matters pertaining to South India let me say a word or two about the Budget in general.

I welcome the deficit financing as presented by the hon. Finance Minister. We have full belief and faith in our Finance Minister that he would never let down the financial condition of India. But my own fears are that such deficit financing will have to be sought year after year for many years to come. The hon. Finance Minister admits that inflation will be there to some extent. To what extent, we do not know. Rs. 742 crores of sterling balances will be used to counteract, to some extent, the inflation that is likely to occur. How far will it be successful? We do not know.

There is also a suggestion that increased production and a drive to maximise savings will mitigate to some extent the inflation that is likely to occur but there also we will be able to gauge at the end of the financial year how far we have been successful.

The hon. Finance Minister is eager to raise the tempo of the economic activities. The Planning Commission are also equally anxious to spend the entire amount allotted in the Budget. But what are our achievements in all these years? Not even forty per cent. of the total planned expenditure has been utilised. Has it been spent wisely and well? Two more years of the Plan are before us. The provision made in the Budget is beyond the ability of the administration to utilise fully. Here a word of caution is necessary. Let not the craving to spend the allotted sum lead to unnecessary and wasteful expenditure. The Public Accounts Committee has toured some of the project areas and they know to a certain extent what the real position is. Let them gather all the information and submit reports periodically—that is, at least once at the beginning of every Session—to this House. The House will be in a position to understand the true nature of things and give some helpful suggestions to the Government and that will also give the necessary drive to push the Plan further.

Regarding the new taxation proposals, the excise duty on footwear and the import duty on betel-nut are going to affect not the rich but the poor classes of people who form the bulk of the nation. Let the hon. Minister put his hands into the bulging pockets of the many who wear coats, trousers, *jibbas*, but let him leave the loin cloth man with his poor sandal to protect his foot and the small receptacle which contains his *pansupari*.

Regarding betel-nut many opinions have been expressed on the floor of this House. I, from the South, know how this betel-nut and *pansupari* is being used by the southerners. It is an ancient habit with them; and is a part of their culture and no house is without its betel leaves and betel-nut. In any ceremony whether it is private or public, distribution of *pansupari* is an inevitable item without which nothing is complete. From adolescence to the last days of their existence in this world, they use this. The arecanut or betel-nut is prepared in various forms in South India. There are many varieties to suit the different tastes of the people there. There are also many men engaged in preparing or curing the betel-nuts for different purposes—for ceremonial purposes and so on. So many

people will suffer if an import duty is levied on the imported product because thereby the local arecanut price will rise and the poor people will really be affected by it. Let me also say something more about it. This *pansupari* is vitally important for the southerners because after each meal they will have to take some leaves and nuts with a doze of calcium. I am a medical man—you can believe me—this much needed calcium is found there and poor people who are deficient in calcium are usually accustomed to this kind of calcium; they take it and absorb it. Apart from that it is a good carbonative and digestive and it is a solace for the poor.

I would also like to mention this. One hon. Member who spoke just before said that it was an apology for meal—it is not an apology; it forms part of it. People, southerners especially, can rather go without a meal to the work-spot or during the working time they can go on without a meal or drink or anything but not without this *pansupari*. This is highly essential and I say that it is a culture of South India to use it. So the duty on this will naturally affect the poor people. That is why I request the hon. Finance Minister to consider and try to bring down at least this particular duty so that the price may not be very high.

Then comes the footwear. Let the hon. Finance Minister consider the hand-made footwear as distinguished from the machine-made one. Because the rougher kinds are usually made by hand and are being used by the poorer classes of people, naturally the hand-made ones must be free from this kind of excise duty. Only the machine-made ones must be taxed and not those worn or made by the poor people.

I would like to say something about artificial silk. I heard recently that after the presentation of the Budget, in Ahmedabad, about forty artificial silk handloom factories have closed down thinking that it would not be profitable for them to produce it. I request the hon. Finance Minister to consider this point of view also.

Some Members yesterday said that soap and some of these articles are luxuries. Soap is not a luxury in the present day. Everybody is using it and is going to use it for a long time to come. The local-made or the hand-made soaps are not charged excise duties, but here I would like to mention that the hand-made soaps have not got a definite composition, The compositions vary with each man, with each variety and so on. These hand-made soaps are not suitable for the body; it is not like clothes where even ordinary and crude varieties can be safely used. The body needs a finer variety of soap so that it may not affect the skin. People are now accustomed to the use of finer soaps for the body and a cruder variety for washing the clothes. It is used not only by the rich people or the middle classes but also by the poor people now. They have taken to the use of soap and so it has come to stay. So, I request the hon. Finance Minister to reconsider and try to take off some of these duties.

The next Five Year Plan is now in the making. The majority of the villages in the South are without proper access by roads—frunk roads, etc.—and there are ever so many things. I represent the Tiruchirapalli District where there is a mighty river, Cauvery. On the one side, the northern side, it is feeding a lot of these fertile lands whereas on the southern side, there is no good water supply system. I would request the Plan-makers to come to the areas concerned and see taluk by taluk and get all the information necessary. I would ask them to put this at least in the next Five Year Plan so that these barren lands are converted into good wet soil. It is easily possible there. Here I would like to mention that the famous Dr. Visvesvarayya had definitely drawn

[Dr. Mathuram]

plans for this area too and his services may be utilised. These plans which are with the Madras State may be called for. The implementation of these plans will go a long way in improving the barren lands in Tiruchi, Pudukkottai and Ramnad districts. All these three districts will be benefited and thousands and thousands of acres and many square miles of land will become cultivated soil and yield good results, even better results than the Tanjore-Cauvery delta. So I would request the planners to consider these plans and have them introduced in the next Plan.

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं कई रोज़ से यहां पर हाउस में तक़रीरें सुनता रहा हूं और इन को सुन कर बहुत आश्चर्य करता रहा हूं कि इन तक़रीरों का फ़ायनैन्स मिनिस्टर साहब के दिल पर क्या असर होता होगा । श्री तुलसीदास किलाचन्द साहब उठते हैं और फरमाते हैं कि हमारे वास्ते, जितने बड़े बड़े कैपिटैलिस्ट हैं, उन के लिये फायनेन्स मिनिस्टर साहब ने ख्याल नहीं रखा । हमारे ऊपर टैक्स बढ़ गये । श्री सोमानी साहब ने भी, गो कि कम ज़ोर से कहा, उसी लहजे को दोहराया । जब मैं श्री राजभोज साहब की तक़रीर को सुनता हूं तो वह कहते हैं कि हमारी बात तो इस सारे भवन में ही नहीं सुनी जाती, न प्राइम मिनिस्टर साहब सुनते हैं और न फायनेन्स मिनिस्टर साहब सुनते हैं । जब श्री नम्बियार साहब की बात सुनता हूं तो वह कहते हैं कि एक हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर दिये और अनएम्पलायमेंट बढ़ती ही जा रही है । अगर दूसरे भाइयों की बात सुनता हूं तो वह कहते हैं कि फायनैन्स मिनिस्टर साहब एक इस तरह के आदमी हैं कि रुपया खर्च करते हैं एक हज़ार और देश में कुछ काम ही नहीं होता । खर्च करने का इरादा वह रखते हैं १२०० करोड़ रुपये का, लेकिन मेरे दोस्तों के ख्याल के मुताबिक़ वह सारा का सारा रुपया व्यर्थ जायगा । इस सिलसिले में मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हम ने बहुत सी कहानियां सुनी हैं । एक कहानी बचपन में पढ़ी थी कि पांच अन्धे आदमी हिन्दुस्तान में एक हाथी को देखने के लिये गये, तो किसी ने कान देखा, किसी ने सूण्ड देखा, किसी ने पूछ देखी, किसी ने पेट देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा । और सब के सब समझ नहीं सके कि क्या चीज़ है, आंखें देखीं कि छोटी सी हैं ।

कई माननीय सदस्य : अन्धे थे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से दोस्त फायनैन्स मिनिस्टर साहब को जिस तरह से देख रहे हैं, वह दुरुस्त नहीं है । कालिदास ने जब रघुकुल का बयान किया तो किस तरह कहा था, फरमाया कि उन लोगों में इनकनसिस्टेंट वर्चुज़ का मजमुआ था । मुझे तो नज़र आता है कि थोड़ा सा हमारे फायनैन्स मिनिस्टर साहब भी उस डिस्क्रिप्शन में आ गये हैं । मैं ने इन चार वर्षों के अन्दर इतना काशस मिनिस्टर और देखा ही नहीं । और मैं तो हमेशा शिकायत ही करता रहा कि फायनैन्स मिनिस्टर साहब बड़े सख्त हैं, जो थैली का मुंह बन्धा हुआ रखते हैं, उस को इतनी मज़बूती से बन्धी रखते हैं कि उस में से कोई कहीं से पैसा निकाल ही नहीं सकता । फायनैन्स मिनिस्टरी के पास से आप पैसा ले लें, यह मुश्किल है । मुझे भी इस का थोड़ा तजुर्बा है । गो संवर्द्धन के सिलसिले में सब चीज़ें पास हो गईं, सब कुछ तय हो गया, लेकिन जब रुपये देने का वक्त आया तो देखा कि वही दिक्कतें मौजूद हैं । लेकिन जब मैं कल सुनता हूं कि श्री मोरे साहब और त्रिवेदी साहब फरमाते थे कि इन पर फौजदारी मुकदमा चलना चाहिये इस बात का, यह तो खर्च ज्यादा करते हैं और

कमाते कम हैं, तो मैं तो हैरान हो जाता हूं कि किस तरह से यह हमारे दोस्त सोचते हैं। मुझे तो यह मालूम होता है कि यह सब की सब बातें दरअस्ल दुरुस्त नहीं हैं, और जैसा कि परसों फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था, यह सारी की सारी बातें मिसकनसीव्ड क्रिटिसिज्म की हैं।

हमारे सामने इस भवन में एक रिजोल्यूशन आया और सारा हाउस कमिट हो गया, फाइव ईयर प्लान की तरफ़। तो जो शख्स उस फाइव ईयर प्लान को आगे चलाता है, जो इस के लिये पांच वर्षों तक के अरसे के लिये रुपया मुहय्या करता है और जो उस नैशनल एफर्ट को पूरा कराने के लिये पैसा देना चाहता है तो मैं तो उस के सामने अपना सिर तसलीम खम करता हूं।

मैं उस के सामने सिर झुकाता हूं : फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो पालिसी इस हाउस में कायम की थी उस को निभाने में उन्होंने पूरी ईमान्दारी से, पूरी एफर्ट से काम लिया। कहा जाता है कि मिड्ल क्लास डूब गई, गरीब भी डूब गये और अमीर भी डूब गये। अगर अमीर और गरीब दोनों डूब गये, तो मैं पूछता हूं कि आखिर तरा कौन ? क्या कोई भी नहीं तरा ? बात यह है कि हर एक आदमी अपने नुक्ते ख्याल से देखता है। असल में सारे का सारा हिन्दुस्तान तरने की तरफ जा रहा है। मुझे यह कहने में जरा भी तामुल नहीं कि यह जो फाइव इअर प्लान है और इस के ऊपर जो रुपया खर्च हो रहा है, यह सब से बड़ा इन्वेस्टमेन्ट देश के लिये है और देश के भले के लिये है। जो बजट इस को पायें तकमील तक पहुंचाता है वह बिल्कुल दुरुस्त है और उस के ऊपर नुक्ता चीनी करना फुजूल है।

आज लोग कहते हैं कि आजकल अन-एम्प्लायमेन्ट बढ़ गया है, कहते हैं कि देश गरीब हो रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेरे जिले हिसार के उस हिस्से में जा कर देखिये जिसे कि भाखरा डैम से पानी मिला है। वहां के लोगों को जा कर देखिये कि उन की क्या हालत है और किस तरह से उन के ऊपर फाइव इअर प्लान का असर हो रहा है। अगर इस में कोई कामयाबी नहीं हो रही है तो कैसे वहां के लोग इतने खुश हो रहे हैं। पंजाब के उस हिस्से में देखिये जहां भाखरा का पानी पहुंचा है, पेप्सू जा कर देखिये। राजपूताने में, उस खुश्क राजपूताने में जहां पानी की शक्ल नहीं दिखाई देती थी, उन सब के वास्ते प्रामिज है कि वहां पानी लाया जाएगा, वहां हरियाली छा जायेगी। खुशहाली आ जायेगी—और सारे इलाक़े की काया पलट जायेगी। जिस वक्त पंजाब का पार्टिशन हुआ, हालत यह थी कि वह बिल्कुल डिफिशिएन्ट सूबा था, वह अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएन्ट नहीं था, लेकिन आज पंजाब हिन्दुस्तान को ९० लाख टन चावल दे रहा है। यह आखिर किस चीज की बदौलत है ? कहा जाता है कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं है, मगर यह २० करोड़ ७९ लाख रुपया किस के लिये खर्च हो रहा है ? क्या यह कामनमैन नहीं हैं ? क्या वह लोग आम शहरी नहीं हैं जिन को हमारे कम्यूनिस्ट दोस्त इतना अजीज समझते हैं यानी इण्डस्ट्रियल लेबरर। मैं नहीं जानता कि और जगह उन की क्या हालत है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे यहां पंजाब में मिड्ल क्लास के लोग भी हैं और इण्डस्ट्रियल लेबरर (labourer) भी हैं। आज कौन सा लेबरर है जोकि दो रुपये रोज से कम पाता है ? मेरे यहां तो इलाके भर में २ रुपये पर भी मामूली मजदूर नहीं मिलता। मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक पंजाब का सवाल है, वहां तक यह पालिसी कामयाब है, बजट भी कामयाब है और गवर्नमेंट की पालिसी भी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कामयाब है। मुझे इस के कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह सब की सब कामयाब हैं और मैं कम से कम अपने इलाके की तरफ से आनरेबुल फ्राइनैन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उन की पालिसी निहायत कामयाब है। मैं चाहता हूं कि उन की यह पालिसी फले और फूले।

इतना कह कर मैं अर्ज करूंगा कि हमें फाइनैन्स मिनिस्टर साहब पर पूरा भरोसा है और मिनिस्टर साहब की डेफिसिट फाइनेंसिंग की पालिसी का भी कायल हूं। मैं ने पिछले बजट के मौके पर कहा था कि अगर कहीं हमारे देशमुख साहब डेफिसिट फाइनेन्सिंग से काम लें तो हमारे देश के वास्ते नेकफाल है। वह इतने काशस हैं कि वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। जब वह शुरू में आये थे तो कहा जाता था कि वह ब्यूरोक्रैट हैं, आई० सी० एस० हैं, लेकिन हम ने घसीट कर उन को कांग्रेसमैन डेमोक्रेट बना दिया। मैं कहता हूं कि उन का यह बहुत बोल्ड बजट है और बहुत ठीक बजट है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर किसी चीज के वास्ते डेफिसिट फाइनेन्सिंग जस्टिफाइड है तो डेवेलपमेन्ट प्रोग्रैम के लिये भी जस्टिफाइड है, और एक एक रुपया जो आप खर्च करेंगे उस के लिये देश की सपोर्ट होगी।

यह कह कर अब मैं टैक्सेशन पर आता हूं। जो तीन चीजें टैक्स लगाने की हैं जब मैं उन की तरफ आता हूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब मैं यह देखता हूं कि इस टैक्स से वह फाइव इअर प्लान को आगे चलावेंगे और इस से प्लान में तरक्की होगी, तो मुझे कोई शिकायत की वजह नहीं मालूम पड़ती। लेकिन मैं जब इस की तरफ देखता हूं तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब २५० करोड़ रुपये का डेफिसिट फाइनेंसिंग करने को तैयार हैं तो वह इन थोड़े से, चन्द करोड़ रुपयों के वास्ते देश के अन्दर बदनामी लेने को क्यों तैयार हैं। लोग कहते हैं कि "जूता हमारा टूट गया, मुझे जूता नहीं मिलेगा, मेरे कपड़े पर कत्तर लग गई, मुझे कपड़ा नहीं मिलेगा।" सब लोगों की अपनी अपनी बात कहने की आदत होती है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं वह नहीं मिलती हैं, और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इतने सनकी हैं कि हम को उन छोटी छोटी चीजों से भी महरूम करना चाहते हैं। क्या हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नहीं जानते कि ऊंची हील का जूता पहिनने से थोड़ी ऊंचाई (stature) भी बढ़ जाती है, कपड़े सभ्यता की निशानी हैं और पान खाने से मुंह रच जाता है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन के अन्दर हद से ज्यादा एहतियात है, वह ऐसे काम कर रहे हैं जिस से देश को और ज्यादा रुपया मिले। उन को इस की फिक्र नहीं है कि वह अनपापुलर हो जायेंगे, लेकिन वह देश के फाइनेन्सेज को साउण्ड बेसिस पर लाने के लिये टैक्स लगा रहे हैं। फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि इस टैक्स लगाने के अन्दर कई गरीब आदमी बेचारे बीच में ही पिस जायेंगे। एक हमारे रिफ्यूजी साहब हैं, उन्हों ने ८००० रुपया लोन लिया है। उस ने एक सोप फैक्ट्री खोली। सिर्फ एक प्रासेस में वह एलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, और कुल ६ आदमी उस में काम करते हैं। वे कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमारा ख्याल नहीं रक्खा। कम से कम ऐसी इण्डस्ट्री जिस के अन्दर १० आदमी से कम लगें और जहां एलेक्ट्रिसिटी यूज भी होती हो, लेकिन १० आदमी से कम हैं, चाहे वह सोप फैक्ट्री हो

या कोई दूसरी फैक्टरी हो, उस पर अगर आप टैक्स लगायेंगे तो आप उसी पर टैक्स लगायेंगे जिस के लिये कि आप सारा फाइव इयर प्लान बना रहे हैं। आप ने टैक्स लगाते वक्त फैक्ट्री की तारीफ जूतों के मुतल्लिक़ तो लिखी परन्तु सोप के लिये यह तारीफ़ लागू नहीं की ।

जनाब वाला, मुझे चन्द बातें और अर्ज़ करनी हैं । मैं सब से पहले कश्मीर के मज़मून पर आता हूं । अर्सा दराज़ हुआ जब मैं पार्लियामेन्ट की तरफ से दो तीन दफा कश्मीर गया और वहां मैं ने जा कर जो देखा उस की आ कर रिपोर्ट भी की । सन् १९५० में मैं ने जब हाउस के अन्दर प्रेज़िडेन्ट साहब के ऐड्रेस पर बहस हो रही थी तो एक मोशन भेजा था । वह मोशन इस तरह से था :

"But regret that there is absence of mention in the Address that the indefinite postponement of the solution of the Kashmir issue and dangling of the remote possibility of a plebiscite being taken by the U.N.O. are causing widespread uneasiness and uncertainty among the people of Kashmir who are of the view that it is the constitutional right of the Kashmir State and people of Kashmir alone to take the decision by plebiscite or in any other manner they like in respect of accession and no obstacle should be placed in their way to take the decision as soon as possible."

श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, चार साल का अर्सा हो चुका जब कि यह ऐमेन्डमेन्ट भेजा था और उसके बाद कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली बनी कश्मीर में और सब कुछ हुआ । आज उस कांस्ट्टुएंट एसेंबली की सिफारिश गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास आ चुकी है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा यह हाल होता कि ६ बरस तक हम को अपनी किस्मत का फैसला न मालूम होता कि हमारा कान्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होगा तो हम कैसा महसूस होता । मैं ने १९५० में महसूस किया कि कश्मीर के लोग बड़े दुखी हैं, वह नहीं जानते कि यू० एन० ओ० में प्लेबिसाइट से क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा । अब जबकि हमारे पास ऐक्सेशन के लिये दर्ख्वास्त आई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान की कंसीडर्ड ओपीनियन यह है कि इस को मंजूर करना चाहिये । मैं और किसी चीज़ में नहीं जाना चाहता । मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर डिमाक्रेसी की कोई वकत हम करते हैं, तो यह चाहिये कि हम ऐक्सेशन मंजूर कर लें और जो दो हज़ार वर्ष से हमारे रिश्ते चले आये हैं, जहां हमारा सब से बड़ा पोएट पैदा हुआ, जहां हमारे पुराने ट्रैडिशन्स व ताल्लुकात हर किस्म के मौजूद हैं, उन से हम जुदा न रहें ।

जनाब की खिदमत में मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं । इस कदर एहतियात से हम देश की भलाई के लिये योजना बना रहे हैं, लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस हाउस में आ कर फरमाते हैं कि आज ग्रेव सिचुएशन है, उस ग्रेव सिचुएशन का कोई भी ज़िक्र या रिफ्लेक्शन हम अपने बजट में नहीं देखते । मैं दरअस्ल उन आदमियों में से नहीं हूं जो यह समझें कि आर्मामेंट रेस हो सकती है, या होना चाहिये न हम इस काबिल हैं कि हमारी एक साल की आमदनी हमें इस काबिल बना सकती है कि हम हर बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकें, लेकिन जहां तक हो सके, मेरी राय है हम लोग डिफेन्स पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें । लेकिन इस डिफेन्स को छोड़ कर एक चीज और रह जाती है जोकि डिफेन्स अगर नहीं, लेकिन डिफेन्स से कम भी नहीं है । वह है हमारा होम डिफेन्स । आज दिल्ली सेक्रेटेरियेट

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और हमारा यह भवन एटोमिक हथियारों के सामने, एअरोप्लेन के सामने क्या हैसियत रखता है ? मैं चाहता हूं कि जहां तक इस दिल्ली की सेक्रेटेरियट का, इस गवर्नमेंट का या पंडित नेहरू और देशमुख साहब की यहां जो वर्क करने की जगह है, उस का जहां तक ताल्लुक है, उन का पूरे से पूरा बचाव किया जाय । यह बचाव कैसे हो सकता है ?

आप लन्दन में जाइये वहां पर कोई हवाई जहाज बम्ब नहीं डाल सकता । मैं चाहता हूं कि ऐसा ही इन्तिज़ाम यहां के लिये किया जाय । यह तो बाद की चीज है कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, लेकिन ताहम जो बार्डर के इलाके हैं उन में सब से पहिले पैनिक होगा । उन इलाके के लोगों को आप गुरिल्ला वारफेयर के लिये ट्रेन करें । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है वहां का एक एक यूथ अपनी जान लड़ा देगा । और यह नहीं होगा कि किसी दुश्मन को पंजाब में कदम रखने की इजाजत दे । पंजाब के जाटों ने टर्की व फ्रांस में जा कर अपनी बहादुरी का सिक्का जमाया । वह आज भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं मगर जब तक आप उन को गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक न तो वह यह समझेंगे कि हम काफी मजबूत हैं और न वह पूरा काम कर सकेंगे । हम भी यह फील करते हैं कि आप टैरीटोरियल फोर्स को बढ़ाइये लेकिन साथ साथ जो बार्डर का एरिया है वहां के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर सिखलाया जाय । मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं वह अकेली मेरी ही राय नहीं है बल्कि वह मेरे सारे इलाके वालों की राय है । इस पर आप जरूर ख्याल फरमावें । तो आप इन दोनों तरह के डिफेन्स का खास ख्याल रखें ।

स्वराज्य मिलने के पहले जब मैं बजट पर बोलता था तो मैं अपनी यार्डस्टिक यह रखता था कि अगर हमारे अछूत भाइयों की तरक्की हुई है तब तो कुछ तरक्की हुई है और नहीं तो तरक्की नहीं हुई है । लेकिन अब मैं ने अपनी वह यार्डस्टिक तबदील कर दी है और मैं देखता हूं कि जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल हम ने रखे हैं उन की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है या नहीं । अगर उस तरफ हमारा कदम बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि हम ने तरक्की की है और अगर नहीं बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि हम ने तरक्की नहीं की है और हमारी तरक्की नहीं हो रही है । आप ने वायदा किया था कि १५ वर्ष के अन्दर हम देश में हिन्दी फैला देंगे । चार वर्ष हो चुके और मुझे यह नजर नहीं आता कि कैसे ११ वर्ष में आप अपना यह वायदा पूरा कर सकेंगे । कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि हमारी लैंग्वेज उरदू हो । अलीगढ़ में इस के लिये एक कानफरेंस की जाती है और यह मांग की जाती है । इस मौके पर इस तरह की फिसीपेरस टेंडेंसी दिखाना मुल्क के हक में किसी तरह अच्छा नहीं हो सकता । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस वक्त खुसूसन इस देश में यह चीज पैदा होना बहुत मुज़िर हो सकता है । हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें बन्द की जायें । आजकल हम रोज सुनते हैं कि इतने मुसलमान वापस आ गये और उन को बसाया गया । हम नहीं चाहते कि हम ने जो कुछ कांस्टीट्यूशन में तै कर दिया है उस के खिलाफ हम जायें और हम समझते हैं कि किसी भी मुसलमान को जोकि इस मुल्क में रहता है वही अख्तियारात हासिल हैं जोकि किसी और को हैं । लेकिन हम बाहर से आने वालों को कब तक इस तरह बसाते चले जायेंगे । क्या ऐसे आदमियों से देश को खतरा नहीं ?

इसी सम्बन्ध में मैं आप की तवज्जह दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं । आप ने वादा किया था कि दस बरस में हम अछूतों को अपने बराबर ले आवेंगे । मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि इस भवन में ऐसा कौन भाई है जो अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सके कि हम इन को अपने बराबर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । जो कुछ हम ने अब तक किया है वह काफी नहीं है । वह कहना कि हम ने अब तक कुछ नहीं किया है, गलत है । हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम ने उन के मुताबिक किया है लेकिन मैं इस रफ्तार को दुगनी और चौगुनी देखना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि एक एक नौकरी जिस के लिये काबिल अछूत लोग मिलें उस में उन को रखा जाये, उन को जमीनें दी जायें । यहां से १५ मील दूर पर ही एक गांव मूलाहेडा नाम में मैं ने देखा कि चिराग के नीचे अंधेरा है । मैं ने देखा कि मूलाहेडा गांव में यहां से १५ मील पर एक हजार गज जमीन में २५ खानदान अछूतों के रहते हैं और उन के साथ उन के जानवर भी रहते हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे साथ उस गांव को चल कर देखें । यह बात नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने उन का ऐसा हाल कर दिया है लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि देश के अन्दर पावरटी की क्या हालत है । हमारे लायक दोस्त हीरेन मुखर्जी ने कहा था कि ट्रावनकोर कोचीन में फी आदमी साढ़े तीन आने की आमदनी है । लेकिन वह नहीं जानते कि एक जमाना था कि जिस को हम ने दो पैसे रोज का काम दे दिया वह उस को ब्लैसिंग मानता था। जो गांव मैं ने बतलाया है अगर आप उस को देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर दुनिया में कहीं हैल हो सकता है तो वह इस जगह पर है । लेकिन मैं बेबस हूं । मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा लेकिन वह उन की हालत की तबदील नहीं कर सकते । मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकते । इसलिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप स्टेप्स लीजिये और किसी को मुकर्रर कीजिये जोकि उन की हालत को तबदील कर सके । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उन की हालत नहीं बदलेगी ।

तीसरी चीज जिस की तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह काऊ स्लाटर का सवाल है । मैं अपने कांस्टीट्यूशन से किसी को बड़ा नहीं समझता, जिस की पाबन्दी मिनिस्टर्ज और कैबिनेट व सब शहरियों पर है । कांस्टीट्यूशन हमारी आखरी चीज है । आप ने दफा ४८ में लिखा है कि जहां तक हो सकेगा हम एग्रीकल्चर के माडर्न मैथड्स को अपनायेंगे । साथ ही यह भी उस में दिया हुआ है कि जहां तक काऊ व काल्ज का सवाल है उस को स्लाटर करना बन्द कर देंगे और उस के अलावा जो दूसरे मिल्च और ड्राफ्ट कैटल हैं उन का स्लाटर भी बन्द कर देंगे । मैं ने इस हाउस में पिछले छै सालों में बड़ी कोशिश की कि इस तरफ तवज्जह दिलाऊं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने कोई तवज्जह न दी बल्कि हमारे एक डिपार्टमेंट ने एक सरकुलर जारी कर दिया जो कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है और (cow slaughter) के हक में है। मुझे खुशी है कि श्री किदवई साहब ने इस हाउस में भी कहा और उन की राय साफ अलफाज में जाहिर हुई है कि वह उस सरकुलर को विदड्रा कर लेंगे । लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप डिमाक्रेसी को सही मानों में समझना चाहते हैं और अगर आप देश की आवाज सुनना चाहते हैं तो आप पूरा कदम उठाइये और स्टेट्स को इस बारे में हिदायत दीजिये । हम कलकत्ते और बम्बई गये और हम ने पाया कि उन स्टेट्स को इस बात का अहसास नहीं है कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उन को क्या करना है । जिस देश के अन्दर कैटल की यह हालत है उस देश के अन्दर २०६९ करोड़ की या इस से भी ज्यादा रकम की स्कीम से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो सकेगा । मैं खुश हूं हमारे कृष्णप्पा साहब ने फरमाया और तसलीम किया कि यह हमारे जानवर हमारी चलती फिरती सिंदरी फैक्टरी और चित्तरंजन हैं । आप ने ग्रो मोर फूड पर तो तकरीबन १०० करोड़ रुपया पिछले चन्द सालों में खर्च किया पर जानवरों पर आप ने ६ लाख ही खर्च किया । मैं ऐसे इलाके से आता हूं कि जहां के लोग गोश्त नहीं खाते और शराब नहीं पीते थे । दो वर्ल्ड लड़ाइयों के ज़माने से कुछ लोग इन का इस्तैमाल करने लगे हैं । अगर मैं वहां के लोगों की बहादुरी का जिक्र करूंगा तो आप के कान खड़े हो जायेंगे और आप महसूस करेंगे कि वैजीटेरियन लोग कितने मज़बूत होते हैं । मैं कहता हूं कि खेती के लिये गौ का पालना तो पहली चीज़ है । पुरानी सरकार ने तो इस तरफ कुछ नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने भी इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है । हम ने गोसम्वर्धन काउंसिल बनाई लेकिन उस को कोई रुपया ही नहीं देता । इस देश के १६ पर सेंट आदमी यह नहीं जानते कि दूध क्या होता है । विलायत में आप देखें कि फी आदमी एक सेर दूध का रोज़ाना इस्तैमाल का औसत है, डेनमार्क में दो सेर का औसत है । ऐसा ही दूसरी जगहों पर भी है । लेकिन हमारे मुल्क में यह औसत पहले ७ छटांक था, वह घट कर पांच छटांक रहा और अब पौने पांच छटांक रह गया है । अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश हरा भरा हो तो जो आप गाय का कत्ल बन्द करने व उस के नसल सुधार पर काफी रुपया खर्च कीजिये कम से कम बीस करोड़ रुपया तो इस बात के लिये खर्च कीजिये—आप की ९००० या १०,००० नेशनल इन्कम में से २५ फीसदी के लिये यह मवेशी ज़िम्मेवार हैं । आप ने एक करोड़ रुपया गोसदनों के लिये रखा है । यह बहुत कम है । लेकिन खर्च इस में से भी कुछ नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने गोसदन खुले हैं । मैं मानता हूं कि सरकार ने कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ४८ में इस पालिसी को माना है कि हम काऊ स्लाटर को बन्द कर दें लेकिन अमल क्या होता है । जब रुपया मांगा जाता है तो कह दिया जाता है कि यह कैटल यूज़लेस हैं । आप नहीं जानते कि कितने लोग इन जानवरों को मैन्योर के लिये ही रखते हैं । मैं मानता हूं कि यह प्राबलम मुश्किल है लेकिन इस को हमें हल तो करना ही है । हमारे प्रेसीडेंट साहब ने हिसार में अपने एड्रेस में कहा कि जो मौजूदा कैटिल हैं उन का सब काम १५ साल में हो जायगा । आप आयन्दा के लिये ऐसी कोशिश करें कि बेकार जानवर पैदा न हों । लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जह नहीं की है । मुझे डर लगता है कि गौ का नाम लिया नहीं कि लोग समझने लगते हैं कि यह तो हिन्दू धर्म की बात है ।

5 P.M.

इस को इकानामिक बेसिस पर देखिये ठीक तरह से देख कर फैसला कीजिये । बछड़ों के वास्ते तो कम से कम जो आप का कांस्टीट्यूशन है, उस में साफ दर्ज है कि उन को नहीं मारा जायगा । उन के बारे में क्या हो रहा है ? आज उन की खालें पहले के मुकाबले में चार गुनी हिन्दुस्तान के बाहर जाती हैं । मैं आप से पूछता हूं कि इस पवित्र कांस्टीट्यूशन की दफ़ा ४८ की किस तरह मिट्टी खराब हो रही है कि चौगुनी ज्यादा इन बछड़ों की खालें हिन्दुस्तान से बाहर जा

रही हैं । इसलिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि आप अवाम की आवाज को सुनें, आप सुनें कि वे लोग क्या कहते हैं कि जिन के वास्ते आप अपील करते हैं कि वह अपने खून का अखिरी कतरा आप को बचाने के लिये दें, अपने देश की हिफाजत के लिये दें । आप उन की आवाज सुनिये । आप देश की आवाज को सुनिये और इन का कत्ल बन्द करिये ।

मैं जनाब का बड़ा मशकूर हूं कि जनाब ने मुझे बोलने का मौका अता फ़रमाया । अब मैं खत्म करता हूं ।

FOURTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up Private Members' Bills and Resolutions.

Shri Altekar (North Satara): With your permission, Sir, I beg to move:

> "That this House agrees with the Fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th March, 1954."

The Committee, after discussion with the Movers of the Resolutions and going through the other aspects, has allotted two hours to the first Resolution of Shri Gidwani regarding encouraging of family planning, two and a half hours to the Resolution by Shri M. S. Gurupadaswamy regarding abolition of the Second Chamber at the Centre, and two hours for the Resolution of Shri Dabhi regarding the introduction of prohibition among the Army, the Navy and the Air Force. It is a simple matter. I commend this Report for the acceptance of the House.

Mr. Deputy-Speaker: The point is this. There are only three Resolutions on the Order Paper today: Shri Gidwani's Resolution regarding family planning, Shri M. S. Gurupadaswamy's Resolution regarding the abolition of the Second Chamber and Shri Dabhi's Resolution regarding the introduction of prohibition in the Army, the Navy and the Air Force. The Committee has allotted two hours for Shri Gidwani's Resolution, two and a half hours for Shri M. S. Gurupadaswamy's Resolution and two hours for Shri Dabhi's resolution.

The question is:

> "That this House agrees with the Fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th March, 1954."

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE.* FAMILY PLANNING

Mr. Deputy-Speaker: Two hours is the time allotted for this. How long does the hon. Minister propose to take?

The Minister of Health (Rajkumari Amrit Kaur): I do not think I shall want more than 15 to 20 minutes to reply.

Shri Gidwani (Thana): Twenty minutes in the beginning and ten minutes at the end for me.

Mr. Deputy-Speaker: We have got one hour and ten minutes. For the other Members, I will allow one Member from each group for 10 minutes.

The Minister of Defence Organisation (Shri Tyagi): In that case, the third Resolution does not come up at all.

Mr. Deputy-Speaker: Shri M. S. Gurupadaswamy may not move the second Resolution.

Shri Tyagi: If he withdraws, that is another matter.